RAJYA SABHA

Friday, 26 July, 1991/4 Sravana, 1913 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

OBITUARY REFERENCE

MR. CHAIRMAN: Before we take up today's agenda, I refer with profound sorrow to the sudden passing away of Thakur Kamakhya Prasad Singh, an ex-Member of this House under tragic circumstances. As per press reports this morning, he was shot dead at his residence in Patna yesterday afternoon.

Thakur Kamakhya Prasad Singh was born in July, 1925 at village and P.O. Kakwara, Bhagalpur, Bihar and had his education at Banka and Bhagalpur. An agriculturists, Thakur Kamakhya Prasad Singh was also connected with the welfare activities to secure justice for Harijans and the poor. He was also associated with various other organisations. He was the Chairman of the State Warehousing Corporation.

He was a Member of the Bihar Legislative Assembly from 1969 to 1971, 1972 to 1978 and 1980 to November, 1983 During his membership of Rajya Sabha from April, 1984 to April, 1990, Thakur Kamakhya Prasad Singh always pleaded the cause of the downtrodden and other weaker sections of the society.

We deeply mourn the passing away of Thakur Kamakhya Prasad Singh.

I request Member to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed.

(Hon. Members then stood in silence for one minute)

MR. CHAIRMAN: Secretary-General will convey to the members of the bereaved family our deep sense of sorrow and profound sympathy.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली की आवास-संबंधी आवश्यकताएं

*181. श्री राम नरेश यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अनुमानत: कितने रिहायशी मकानों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) उनमें से कितने लोगों को सरकार उक्त अवधि में आवास सुविधा उपलब्ध करा पायेगी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) DDA has estimated the requirement of 8.25 lakh dwelling units during 1990-95 keeping in view the various commitments and the shifting of jhuggi families from the priority project sites.

(b) Keeping the estimated requirement in view, the DDA has formulated plans to provide 7.5 lakh additional dwelling units during this period through the efforts of public, private and cooperative sectors.

श्री राम नरेश यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह संतोषजनक नहीं है । यह मैं इसलिये कहा रहा हूं कि दिल्ली की जनसंख्या 1981 में जहां 62 लाख से भी अधिक हो गयी थी, वहां 1991 में यह बढ़कर 93 लाख 70 हजार 475 हो गयी है, और झुग्गी-झोंपड़ियों की संख्या 1981 में 17.3 लाख थी, तो इस समय यह बढ़कर 24 से 25 लाख के बीच में हो गयी है । इस समय यह स्थिति है कि ये लोग किस तरह से गंदे स्थानों पर और गन्दी बस्तियों में रहते हैं जहां पर बेसिक आवश्यकतायें भी नहीं हैं । मजबूर होकर गरीबी के कारण किसी तरह से ये लोग अपनी

जिन्दगी बसर कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में यह जो आंकड़े 18.25 लाख बताये गये हैं, इस संबंध में मेरा प्रश्न यह था कि अनुमानत: कितने रिहायशी मकानों की आवश्यकता होगी । इस बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखकर जिस तरह से झुग्गी-झोंपड़ियों में रहने वालों का दिन प्रतिदिन दिल्ली पर बोझ बढ़ता जा रहा है और गांवों से भाग कर लोग दिल्ली में निवास कर रहे हैं ..... (व्यवधान) ।

श्री सभापति : क्या आप यह पूछ रहे हैं कि यह जो कैलकुलेशन किया गया है वह किस बेसिस पर किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े दिये गये हैं, वह किस आधार पर दिये गये हैं ? क्या फिर से कोई ऐसा सर्वेक्षण करेंगे ताकि यह मालूम हो सके कि दिल्ली में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनके पास आज भी कोई मकान नहीं है और ऐसे लोगों के लिये मकानों की व्यवस्था करनी होगी, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं । यह मेरे प्रश्न का (अ) भाग है और (ब) भाग में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने 8.25 लाख रिहायशी एकक बनाने की बात कही है तो प्रश्न यह है कि 90 से 95 के बीच में बनाना चाहते हैं । 90–91 तो समाप्त हो चुका है और 91–92 वर्ष चल रहा है । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में 90–91 में आपने कितनी आवास व्यवस्था कर ली है और 91–92 जो चल रहा है इसमें कितने आवासों की व्यवस्था करने की आपकी योजना है ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : सभापति महोदय, माननीय मेंबर ने अभी बताया कि दिल्ली की जो आबादी है वह बढ़ गई है और उसके बढ़ने के बजूहात को भी उन्होंने बताया है और यह भी बताया है कि 9370475 दिल्ली की आबादी हो गई है और यहां पर 8.25 लाख जो है वह रहने की यूनिट्स है । श्रीमान्, इसको देखते हुए सरकार के दिल्ली का एक प्लान डेवलपमेंट ही शुरू नहीं किया बल्कि एक हाउसिंग स्टाक भी तैयार किया है । लेकिन यहां की आबादी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रही है । बाहर से लोग आते है, ट्रेडर्स आते हैं, रोजमर्रा लोग आते है । इसलिये यहां कमी है और इसके लिये जितनी हम कोशिश कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारी डिमाड बढ़ती जा रही है । इस वक्त 4.5 लाख की कमी है, जो ब्रेक-अप बताया गया है उसके अनुसार नेचुरल ग्रोथ जो है वह 1.75 का होगा । जो लोग यहां आते जाते हैं, माइग्रेट ड्वलिंग यूनिट, इसके लिये 2 लाख यूनिट्स हमको बनानी है । अब डी०डी०ए० ने इस कमी को पूरा करने के लिये ताकि इनके रहने का बंदोबस्त हो, रोहणी में प्लाट बनाये हैं । इनमें एक अंबेडकर आवास योजना है जो कि कम पैसे वालों के लिये है और साथ ही स्लम विंग भी बनाया है और स्लम कटराज भी बनाये गये हैं और यह कोशिश की गई है, यह बात ध्यान में रखी गई है कि मिडिल इनकम ग्रुप के लिये और जिनकी आमदनी कम है उनके लिये 60 प्रतिशत फ्लैट्स और 74 प्रतिशत प्लाट, जो लो इनकम ग्रुप के हैं उनके लिये रखे जांय । इसमें स्लम विंग स्कीम के तहत 20185 स्लम टेन मेंट्स बनाये गय हैं ।

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, माननीय मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया । मैंने यह पूछा था कि दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदया इस बात का सर्वे करायेंगी कि दिल्ली में इस समय कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिये रहने की, आवास की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि यह फिगर जो आपने दी है वह जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है । एक तो इसका उत्तर नहीं आया । मान्यवर, मैंने दूसरा प्रश्न यह पूछा था कि 90–91 में आपने कितने बनवाये हैं और 91–92 में क्या लक्ष्य रखा है । इन दोनों सवालों के जवाब नहीं आये । आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मान्यवर दिलवा दें, उसके बाद मैं दूसरा प्रश्न करूंगा ।

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, during 1990-91, the DDA has constructed and completed 8,846 houses up to 31st March against the target of 12,600 houses. During the same period, a total of 15,092 flats were allotted to 31st March 1991.

MR. CHAIRMAN: But he wants to know what your target is for 1991-92.

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, our estimated target for 1991-92 is 19,000.

MR. CHAIRMAN: Nineteen thousand plots? These are dwelling houses or plots? Are they plots to be allotted or housing units?

SHRI M. ARUNACHALAM: flats Sir.

श्री राम नरेश यादव : यह प्लाट आप दे रहे हैं या मकान दे रहे हैं । आप उनके रहने के लिये किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, एक तो मैं यह जानना चाहता हूं । मेरा दूसरा सवाल है सर्वे कराने के बारे में, इसका कोई उत्तर नहीं आया मान्यवर ।

MR. CHAIRMAN: Are you going to have any survey or have you done any survey already?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, we are in the process of doing it.

MR. CHAIRMAN: Good.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, मंत्री महोदया ने उत्तर के भाग (ख) में यह कहा है कि सार्वजनिक, निजी और सहकारिता क्षेत्रों के प्रयासों के माध्यम से इस अवधि के दौरान 7.5 लाख अतिरिक्त रिहायशी एकक मुहैया कराने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने योजनाएं प्रतिपादित की हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 7.5 लाख अतिरिक्त रिहायशी एकक मुहैया कराने के लिए योजना बनाई है वह क्या है और उसमें सार्वजनिक क्षेत्रों में कितने रिहायशी एकक बनाने की योजना है, निजी और सहकारिता क्षेत्रों में अलग-अलग कितने रिहायशी एकक बनाने की योजना है तथा इस पर कितने करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है ?

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, the answer has been given in part (b). This estimate is for 1990—95. This is in the public, private and co-operative sectors.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, मैं अलग अलग जानना चाहता हूं कि आखिर पब्लिक सेक्टर में कितने हैं, निजी क्षेत्र में कितने रिहायशी एकक बनाने की योजना है । सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिस आधार पर पता लग सके ?

SHRI M. ARUNACHALAM: Sir, I will collect the information and furnish it to the Member.

MR. CHAIRMAN: He will require notice.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Sir, may I know from the hon. Minister whether 2,000 allottees under the Rohini and Kundli scheme were asked to pay more because there was escalation in the cost due to some default? Some allottees have gone to the High Court. May I know from the hon. Minister whether the allottees at Rohini and Kundli schemes will be given at the same cost at which it was advertised or they will be asked to pay the escalated cost also?

SHRIMATI SHEILA KAUL: I am not able to catch his point. Would he repeat it?

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I will be more specific. There were nearly 2,000 allottees in the Rohini and the Kundli schemes. While advertising, one particular amount was asked to be paid. While allotting them, the cost of escalation was also included and they were asked to pay more. Now, I want to know from the hon. Minister at which cost they are going to be allotted. At the original cost or the new cost?

SHRIMATI SHEILA KAUL: Sir, for this I require a separate notice.

SHRI JAGMOHAN: Sir, there was a scheme of large scale acquisition, develop-

ment and disposal of land in Delhi. It was part of the Delhi Master Plan. Under that scheme, the land was being acquired on a large scale on which housing colonies were being built. I would like to know as to how much land has been acquired during the last five years. That is part (1) of the question. The second is, all the housing which you have projected and which is proposed to be constructed, on which lands are they going to be constructed because all the lands have been encroached upon. And even the lands which were acquired are in somebody else's occupation. How are you going to construct all the houses which you have mentioned?

श्रीमती शीला कौल : हम लोग कोशिश में है कि जो जमीनें खाली पड़ी हुई है उनको एक्वायरक रें। ऐसा कर के हम नयी पालिसी बनाएंगे जिसमे नये घर हम बना सकें ।

श्री जगमोहन : आपने पिछले पांच सालों में कितनी जमीन एक्वायर की है (**व्यवधान**) अच्छा यह बता दीजिये कि वर्ष 1990–91 में कितनी जमीन एक्वायर हुई है जिसके ऊपर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं (**व्यवधान**)

श्रीमती शीला कौल : 31–3–91 तक 63 हजार एकड़ जमीन दिल्ली प्रशासन ने एक्वायर की है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहतीं हूं कि गृह निर्माण के क्षेत्र में डी०डी०ए० की जो इजारेदारी है दिल्ली में, उसके चलते घरों और जमीनों के दामों में बेइन्तहा वृद्धि होती जा रही है । क्या सरकार डी०डी०ए० की इजारेदारी को तोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

इसके अलावा सरकार जहां कह रही कि राष्ट्रीय राजधानी के ढ़ांचे के पुनर्गठन पर विचार कर रही है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि रोज अखबारों में आप देखते हैं कि जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बड़े-बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते हैं कि वह हस्तिनापुर नाम के एक विशाल नगर पर निर्माण करने जा रहे हैं, जिसकी दिल्ली से दूरी सिर्फ ज़ीरो किलोमीटर की है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या सरकार की नजर जी०डी०ए० की ओर है ? . . . (**व्यवधान**) सभापति जी, मैंने यह सवाल किया था कि क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी के ढ़ांचे के पुनर्गठन पर विचार कर रही है ?

SMT. SHEILA KAUL: She has asked about the reconstitution of Delhi. How you can reconstitute Delhi? I don't know what is the question.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैंने जो सवाल पूछा था, उसका जवाब भी नहीं दिया कि डी०डी०ए० की इजारेदारी तोड़ने के लिए क्या सरकार किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है या नहीं ?

MR. CHAIRMAN: She is against the monopoly of DDA. She wants to know whether you are going to do away with the monopoly of DDA. यही है न आपका सवाल ।

SMT. SHEILA KAUL: If the hon. Member wants to know what we are going to do about DDA, I may inform the House that future plans for DDA are under our active consideration.

श्री शांति त्यागी : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आठवीं योजना में जो आवासीय कालोनियां बनेंगी, उनकी लोकेशन क्या दिल्ली क्षेत्र में रहेगी, या आसपास में जो एन०सी आर० के क्षेत्र हैं, उनमें भी उनका निर्माण किया जाएगा ?

मैं जानना चाहता हूं कि इन आवासीय योजनाओं में जो दिल्ली में बनेंगी या एन० सी आर० के क्षेत्र में एल०आई०जी० और एम०आई०जी के जो भवन बनेंगे, उनकी अनुमानित कीमत क्या होगी ? मंत्री जी इसका ठीक से उत्तर दें, क्योंकि दिल्ली का बोझ घटाने के लिए आप इन कालोनीज को एन०सी०आर० के क्षेत्र में भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ? नम्बर एक ? और दूसरे इनकी अनुमानित कीमत क्या होगी ।

श्रीमती **शीला कौल** : जो नेशनल कैपिटल रीजन का प्रोग्राम है, इसके बारे में हम इसको बहुत विस्तार से देख रहे हैं और इसके लिए हमारा जो प्रोग्राम है मुख्तलिफ चीजों का, मल्टिप्लिंग का तथा और चीजों का, रेलवे लाईन और सड़क बनाने का, हम यह चाहते हैं कि एन०सी०आर० में कि जो आबादी है जोकि दिल्ली में आ रही है, यह दिल्ली से दूर रहे और वहां जाकर नये घर बनाये जायें। यह जरूरी है जो हमने सोचा था कि जमीनों पर जो घर बनायेंगे, उनकी एक कीमत होगी। पर क्योंकि सब चीजों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो जरूरी है कि घर बनाने की जो कीमतें हैं, वह भी बढ़ी होंगी। ... (**व्यवधान**)

श्री अजीत जोगी : इन्होंने मकान के बारे में पूछा है। ... (**व्यवधान**)

श्री शांति त्यागी : सोनीपत में बनाइये।

श्रीमती शीला कौल : जो डी०डी०ए० है यह केवल दिल्ली में बनायेगा, कैपिटल रीजन में नहीं बनायेगा।

श्री सिकन्दर बख्त : सदर साहब, जब मैं हाजिर हुआ, तो मंत्री साहिबा की जबान से मैंने "जमीन एक्वायर कर रहे हैं," की बात सुनी।

श्री सभापति : पूरा सवाल नहीं सुना।

श्री सिकन्दर बख्त : जी नहीं इतना ही काफी है।

श्री सभापति : पर यह गलत चीज है। ... (**व्यवधान**)

श्री सिकन्दर बख्त : मैं खाली यह जानना चाहता हूं कि सेक्शन 4 के मातहत जिन जमीनों को आपने नोटिफाई कर रखा है, उनमें से कितनी जमीनें आपने सेक्शन 6 के मातहत कर ली हैं? सेक्शन 4 के मातहत कितने बरस, बरसों पहले से एक्वायर किया है आपने और आज जो एक्वायर करती हैं [illegible]

मेरा दूसरा सवाल, मैं नेशनल केपिटल रीजन, जो आपने फरमाया, वह बाद में करूंगा।

SMT. SHEILA KAUL: Sir, for this I will need notice.

श्री सिकन्दर बख्त : नेशनल कैपिटल रीजन के लिए पूछ लूं, आपसे आपसे अर्ज किया था।

श्री **सभापति** : आप दो सप्लीमेंटरी नहीं कुछ पूछ सकते हैं, एक पूछ सकते हैं।

छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का रायगढ़ तक विस्तार

*182. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्तमान में बिलासपुर से अमृतसर के बीच चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को रायगढ़ या झारसुगडा तक चलाने की मांग के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त गाड़ी का कब तक विस्तार करने का विचार रखती है।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes Sir.

(b) It is not proposed to extend 8237/8238 Chhatisgarh Express upto Raigarh or Jharsuguda.

श्री लक्खीराम अग्रवाल : सभापति जी, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जिस ट्रेन का नाम रखा गया है, उसका अधिकांश हिस्सा बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा जिला है और जहां आदिवासी बहुल [illegible] वहां इसे विस्तार करने में